भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3145
उत्तर दिनांक 11/03/2026 को दिया गया

समुद्र तटों में खनिज

3145. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या परमाणु ऊर्जा निदेशालय ने आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में समुद्र तटों, लाल रेत आदि में खनिजों का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त राज्यों में पाए गए खनिजों का ब्यौरा क्या है और उनकी मात्रा कितनी है;

(ग) केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा की गई इस घोषणा कि दुर्लभ मृदा गलियारे का प्रयोग दुर्लभ मृदा खनिजों के खनन, प्रसंस्करण और विनिर्माण के लिए होगा, से देश को इनके निष्कर्षण में किस प्रकार मदद मिलेगी; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार, देश में समुद्र तटों से दुर्लभ मृदा खनिजों के निष्कर्षण के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है और दुर्लभ मृदा खनिजों के अन्वेषण की क्या स्थिति है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) हाँ, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की एक संघटक इकाई, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ भागों में लाल (टेरी) और तटीय समुद्री तट बालू में समुद्र तटीय बालू खनिज (बीएसएम) के संसाधन स्थापित किए हैं।

(ख) दिसंबर, 2025 तक देश में बीएसएम और अंतर्देशीय प्लेसर सहित आर्थिक रूप से भारी खनिजों के कुल संसाधन 1,309.42 मिलियन टन (1,309 मिलियन टन तक पूर्णांकित) हैं। दिसंबर, 2025 तक कुल भारी खनिज (टीएचएम) संसाधन (मिलियन टन) का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	निक्षेप	इल्मेनाइट	रूटाइल	ल्यूकोक्सिन	मोनाज़ाइट	ज़िरकॉन	गार्नेट	सिलिमेनाइट	टीएचएम
उड़ीसा	13	172.25	7.19	0.94	3.22	6.00	71.60	90.17	**351.36**
आंध्र प्रदेश	25	178.75	11.46	3.64	4.05	12.75	67.30	81.85	**359.79**
तमिलनाडु	54	191.29	8.35	6.56	2.55	10.75	71.15	39.99	**330.64**
केरल	35	144.02	8.74	8.23	1.84	7.96	7.38	64.72	**242.88**

महाराष्ट्र	5	5.50	0.01	0.06	0.004	0.03	0.02	0.01	**5.64**
गुजरात	2	11.64	0.03	0.33	0.07	0.06	0.38	0.04	**12.53**
पश्चिम बंगाल	1	2.05	0.19	-	1.20	0.38	-	1.63	**5.45**
झारखंड	1	0.73	0.01	-	0.21	0.08	-	0.08	**1.12**
कुल	**136**	**706.24**	**35.98**	**19.75**	**13.15**	**38.00**	**217.83**	**278.48**	**1,309.42**

(ग) केंद्रीय बजट 2026 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध तटीय राज्यों में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ मृदा गलियारे (कॉरिडोर) स्थापित करने हेतु समर्थन देने की घोषणा की गई। इन दुर्लभ मृदा गलियारों का उद्देश्य NdPr (नियोडिमियम-प्रसेओडिमियम) और समेरियम ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाकर तथा आरई चुम्बकों के उत्पादन की घरेलू मांग को बढ़ावा देकर भारत में एक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी दुर्लभ मृदा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है और साथ ही टाइटेनियम और जिरकोनियम आदि की मूल्य श्रृंखला में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना है। इन समर्पित आरई गलियारों में भारत को दुर्लभ मृदा, टाइटेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों के मूल्य संवर्धन के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है - जो औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय रणनीतिक आवश्यकताओं दोनों को पूरा करेगा।

(घ) मोनाज़ाइट, भारत में ज्ञात दुर्लभ मृदा युक्त खनिज है। यह छह अन्य समुद्र तटीय बालू भारी खनिजों के साथ संबद्ध रूप में पाया जाता है। रेडियोसक्रिय स्रोत के कारण, तटीय समुद्री तटों से मोनाज़ाइट का निष्कर्षण लंबा, जटिल और महंगा है। मोनाज़ाइट का खनन एएमडी द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाता है जो विभिन्न वैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित सीमाओं पर भी आधारित होता है। तटीय क्षेत्रों में घनी आबादी, नियामक अनुपालन की समय-सीमा और स्थिरता से संबंधित आवश्यकताएं इस प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना देती है। तटीय समुद्री तटों में एक विशेष निक्षेप से दुर्लभ मृदा खनिजों के निष्कर्षण के लिए आवश्यक अस्थायी समयावधि को संभावित पट्टेदार के नामांकन की तारीख से वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने, खनन पट्टा विलेख निष्पादित करने और अंततः निक्षेप को प्रचालन कार्य करने तक 4-5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। एएमडी आंध्र प्रदेश के डॉ. अम्बेडकर कोनासीमा जिले, ओडिशा के पुरी जिले और तमिलनाडु के तूत्तुक्कड़ी जिले के कुछ भागों में समुद्र तटीय बालू निक्षेप में मोनाज़ाइट (आरईई और थोरियम का एक खनिज) के अतिरिक्त संसाधन निर्धारित करने के लिए वर्तमान में अन्वेषण कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, एएमडी राजस्थान के जोधपुर, बालोतरा और उदयपुर जिलों, गुजरात में छोटा उदेपुर जिला; तमिलनाडु में सलेम जिला; और तेलंगाना में वारंगल और सूर्यपेट जिले के कुछ भागों में कठोर शैल इलाकों में आरईई संसाधनों के संवर्धन के लिए भी अन्वेषण कार्य कर रहा है। ।

*****